महोदय, आपसे आग्रह है कि आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कानपुर आउटर रिंग रोड के लिए अंशधारिता को अविलम्ब जारी करें, जिससे सड़क निर्माण हो सके और कानपुर में लगने वाला जाम समाप्त हो, धन्यवाद।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

Demand for approval of the proposal for development in the vicinity of Defence establishments in Maharashtra

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, the proposal dated 03.03.2017 sent by the hon. Chief Minister of Maharashtra to the hon. Defence Minister, Government of India regarding development permission in the vicinity of Defence establishments is still awaiting response from Government of India despite the lapse of sufficient time and the matter being of the public importance.

Therefore, through this august House, I urge that urgent and suitable directions may please be issued to the Government of India to consider the aforesaid proposal and reply to the Maharashtra Government at the earliest.

Demand for execution of Jharia Master Plan including BCCL Coal Mining area through a Central Agency

श्री महेश पोद्दार (झारखंड): महोदय, बीसीसीएल कोयला खनन क्षेत्र के अन्तर्गत झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र में भूमिगत आग और भू-धंसान को नियंत्रित करने तथा इससे प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास के लिए झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी गयी है, जिसे 12 वर्षों की अवधि के पश्चात् इसी वर्ष, अर्थात् 2021 में पूरा किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। भारत सरकार ने इसके लिए पर्याप्त निधि का आवंटन भी किया है। झरिया मास्टर प्लान का क्रियान्वयन झारखंड राज्य सरकार के प्राधिकार झरिया पुनर्वास और विकास प्राधिकरण (जरेडा) द्वारा किया जा रहा है, जिसकी प्रगति अत्यन्त धीमी है। विगत 12 वर्षों के अनुभव को देखते हुए इस परियोजना का क्रियान्वयन किसी केन्द्रीय एजेंसी को सौंपना और 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के साथ अभिषरण (कन्वर्जेन्स) कर एक नया शहर विकसित करना श्रेयस्कर होगा। मैं इस विषय को सदन में विशेष उल्लेख के माध्यम से रखना चाहता हूँ।